संसद के समक्ष अभिभाषण — 25 फरवरी 2008

लोक सभा	-	चौदहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत की राष्ट्रपति	-	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री सोमनाथ चटर्जी

माननीय सदस्यगण,

मैं आप सभी का और देश की जनता का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। संसद का यह अधिवेशन ऐसे समय पर हो रहा है जब अर्थव्यवस्था प्रगति पर है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है कि आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया सामाजिक रूप से समावेशी, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और पर्यावरणीय रूप से अक्षुण्ण हो। मेरी सरकार द्वारा किए गए उपायों ने समावेशी विकास का आवश्यक ढांचा तैयार कर लिया है।

विकास प्रक्रिया को सामाजिक रूप से समावेशी और क्षेत्रीय रूप से संतुलित बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इनमें, विकास में ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए–भारत निर्माण; गरीबी की पीड़ा को कम करने के लिए और मूलभूत आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम; हमारे बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराने एवं उनकी क्षमताओं को मूर्त रूप देने के लिए–सर्वशिक्षा अभियान जो सार्वभौमिक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम द्वारा और सुदृढ़ किया गया है; ग्रामीण निर्धनों को मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सामाजिक रूप से समावेशी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शामिल हैं। विकास प्रक्रिया को और अधिक भागीदारीयुक्त संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रही है और सूचना का अधिकार अधिनियम नामक एक अनुस्मरणीय कानून बनाया गया है।

मेरी सरकार की "समावेशी विकास" की कार्यनीति आर्थिक विकास में आई तेजी से समर्थ हुई है और इसने आर्थिक विकास को त्वरित करने में योगदान भी किया है। इतिहास में पहली बार, भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार चार वर्षों से लगभग 9.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विकास हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के 35 प्रतिशत से अधिक की ऐतिहासिक उच्च निवेश दर और सकल घरेलू उत्पाद के 34 प्रतिशत से अधिक की बचत दर हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई गतिशीलता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवावर्ग की रचनात्मकता, उद्यमिता और कड़ी मेहनत आने वाले वर्षों में इन उच्च दरों को बनाए रखने में सक्षम होगी।

तेल की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और खाद्य पदार्थों सहित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के परिप्रेक्ष्य में यह उपलब्धि और भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का यह सतत प्रयास रहेगा कि कीमतों को नियंत्रण में रखते हुए विकास को बनाए रखा जाए। मेरी सरकार ने भारतीय उपभोक्ता को इन वैश्विक मुद्रास्फीतिक रुझानों से बनाए रखने की कोशिश की है। विगत दो वर्षों में विश्व में कच्चे तेल की कीमतें लगभग दोगुनी होकर 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल की अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं, तब भी मेरी सरकार ने घरेलू उपभोक्ता पर पड़े प्रभाव को सीमित रखा है।

समावेशी विकास के ढांचे को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के जरिए और मजबूती मिली है। इस योजना में समूचे राष्ट्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जिसे इस प्रकार प्राप्त किया जाना है ताकि यह गुणवत्तायुक्त शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के लिए समान अवसर प्रदान करे, अस्वस्थता के भार से लोगों को निजात दिलाए और भेदभाव मिटाए।

प्रमुख क्षेत्रों को दी जाने वाली केंद्रीय सकल बजटीय सहायता का भाग पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा पर होने वाला परिव्यय 10वीं योजना में केंद्रीय सकल बजटीय सहायता के 7.68 प्रतिशत से बढ़कर 11वीं योजना में 19 प्रतिशत से अधिक हो गया है। कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर होने वाले परिव्यय को तिगुना कर दिया गया है। शिक्षा को शामिल करते हुए, ये क्षेत्र केंद्रीय सकल बजटीय सहायता का आधे से अधिक हिस्सा प्राप्त करते हैं। जबकि दसवीं योजना में यह एक-तिहाई से भी कम था। योजना की प्राथमिकताओं में यह एक बृहत संरचनात्मक परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य असमानताओं को कम करना और जनता को सशक्त बनाना है।

इस योजना में, अवसंरचना में कुल वार्षिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से बढ़कर 9 प्रतिशत होने की आशा है। सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा और इसे, जहां व्यवहार्य होगा,

निजी निवेश से पूरित किया जाएगा। मेरी सरकार ऐसे समूहों और क्षेत्रों, जो हाशिए पर हैं, को विकास की प्रक्रियाओं से लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों को बढ़ाएगी।

मेरी सरकार हमारे किसानों की ओर विशेष ध्यान दे रही है तथा इसने कृषि में सार्वजनिक निवेश में आई गिरावट के रुख को पलट दिया है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कृषि ऋण को तीन वर्षों में दुगुना करने के तय लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ा जा चुका है। 2007-08 के लिए निर्धारित 2,25,000 करोड़ रु. का लक्ष्य पहले ही दिसम्बर, 2007 तक प्राप्त किया जा चुका है। सरकार ने ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना का पुनरुत्थान शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रो. आर. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कृषि ऋणग्रस्तता पर एक विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की थी। इसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है तथा इसकी सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

"वित्तीय तौर पर वंचित" जनता को औपचारिक बैंक व्यवस्था के भीतर लाने के लिए बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे इस प्रयोजन हेतु स्वयं-सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और अन्य नागरिक समाज संगठनों की सेवाओं का उपयोग करें। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक स्वयं-सहायता समूहों की मदद की जा रही है और स्वरोजगारियों में 52 प्रतिशत महिलाएं हैं। सरकार ने सूक्ष्म वित्तीय सेक्टर (विकास और विनियमन) विधेयक भी संसद में प्रस्तुत कर दिया है। स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, शहरी गरीबों, विशेषकर महिलाओं के दक्षता विकास और रोजगार के लिए अवसर प्रदान कर रही है।

मेरी सरकार ने हाल में कृषि क्षेत्र के लिए दो बड़ी पहलें की हैं: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 11वीं योजना अवधि में चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है। फार्म पुनरुत्थान के लिए 25,000 करोड़ रु. के परिव्यय वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य 11वीं योजना में इस क्षेत्र में और निवेश करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देकर कृषि विकास को 4 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

मेरी सरकार के प्रयासों से कृषि उत्पादन में भरपूर वृद्धि हुई है। कृषि, सिंचाई और जल संसाधनों, जिनमें एक बड़ा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम शामिल है, के सम्मिलित संसाधन 10वीं योजना में 46,131 करोड़ रु. से बढ़कर 11वीं योजना में 1,38,548 करोड़ रु. हो जाएंगे। विगत चार वर्षों में मेरी सरकार ने गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में क्रमशः 50 प्रतिशत से अधिक और लगभग 33 प्रतिशत की अभूतपूर्व त्वरित वृद्धि की है।

मेरी सरकार का लक्ष्य 2015 तक प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार में तीन गुना वृद्धि करना और वैश्विक व्यापार में इसका हिस्सा दोगुना करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 30 मेगा फूड पार्क और एक इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन स्थापित की जाएगी। इस क्षेत्र के लिए ज्ञान संस्था के रूप में कुंडली में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने शिक्षा में पहुंच को बढ़ाकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर अत्यधिक जोर दिया है। छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जातियों के लगभग 30 लाख बच्चों को लगभग 900 करोड़ रु. की राशि तथा 10 लाख से अधिक जनजातीय बच्चों को 225 करोड़ रु. से अधिक की राशि दी गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की विशेष कोचिंग संबंधी स्कीमों को सक्रियता से क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे जनजातीय समुदायों की कला, संस्कृति, परंपरा, भाषाओं, रीति-रिवाजों और चिकित्सीय पद्धतियों में अध्ययन और अनुसंधान तथा जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम एक ऐतिहासिक विधान है जिसका उद्देश्य जनजातीय और परंपरागत वनवासियों की विगत वंचनाओं को दूर करना तथा भूमि पर उनके अधिकारों को उन्हें पुनः प्रदान करना है। राज्य सरकारों से इस अधिनियम के उपबंधों को शीघ्रता से क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जो हमारे श्रमिक बल का अधिकांश भाग है, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मेरी सरकार ने असंगठित सेक्टर सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया है। असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार के लिए 30,000 रु. की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, पहले वर्ष में ही ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लगभग एक करोड़ परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए आम आदमी बीमा योजना और गरीबी रेखा से नीचे तथा 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को 200 रु. प्रतिमाह पेंशन देने के लिए–इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम प्रारंभ की गई है। सरकार ने राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी को भी 66 रु. से बढ़ाकर 80 रु. प्रतिदिन कर दिया है। श्रमिकों को बोनस की अदायगी की पात्रता सीमा को 3500 रु. से बढ़ाकर 10,000 रु. प्रतिमाह कर दिया है। भवन-निर्माण ठेकेदारों द्वारा नियुक्त श्रमिकों को भी बोनस के भुगतान के लिए पात्र बनाया गया है।

मेरी सरकार ने विकास परियोजनाओं के कारण अपनी भूमि से विस्थापित लोगों की चिरकालिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अक्तूबर, 2007 से एक राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति लागू की है। इस नीति में अनैच्छिक विस्थापन उत्पन्न करने वाली सभी परियोजनाओं के संबंध में मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान है। इस नीति को सांविधिक समर्थन प्रदान करने के लिए पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2007 और भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2007 भी संसद में पेश किए जा चुके हैं।

समावेशी विकास के लिए समावेशी शासन की जरूरत होती है। पंचायती राज इसके लिए प्रमुख उपकरण है। सरकार ने सुपुर्दगी व्यवस्था को पंचायतों के माध्यम से कार्य करने के लिए दिशानिर्देशित करने के अलावा स्थानीय विकास योजना को सहारा देने के लिए बंधनमुक्त निधियों के जरिए पंचायती राज को सुदृढ़ किया है। क्षेत्रीय असंतुलनों की समस्या का समाधान करने के लिए मेरी सरकार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा अल्प विकसित क्षेत्रों की सहायता कर रही है।

मेरी सरकार कमजोर वर्गों के नागरिकों को सिविल और आपराधिक, दोनों प्रकार के मामलों में न्याय, उनकी चौखट पर ही उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने हेतु एक विधान लाई है।

मेरी सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रधान मंत्री के नये पंद्रह सूत्री कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यक्रमों का लाभ अल्पसंख्यकों को समतापूर्वक मिले। निर्दिष्ट अनुपात में विकास परियोजनाएं अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्थित होंगी और जहां संभव होगा, विभिन्न स्कीमों के तहत उद्देश्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए विनिर्दिष्ट होगा। अल्पसंख्यकों की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिए सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 11वीं योजना में पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन पर आधारित छात्रवृत्ति के लिए 800 करोड़ रु. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए लगभग 3300 करोड़ रु. और 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के विकास के लिए 3780 करोड़ रु. का प्रावधान है। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए जाने वाले प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के अनुपात को वर्तमान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। समावेशी विकास के ढांचे के लिए ये पहले महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

समाज में महिलाओं का बराबर का योगदान है। स्त्री साक्षरता द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण सामाजिक क्षेत्र में हमारे लिए एकमात्र सबसे बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्त्री साक्षरता में तेजी लाने को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाएगा। भेदभावपूर्ण विधान को हटाकर, विद्यमान विधान को संशोधित करके और ऐसा नया

विधान बनाकर जो महिलाओं को मकान और भूमि जैसी परिसंपत्तियों में समान मालिकाना अधिकार प्रदान करता हो, हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पूर्ण कानूनी समानता के और निकट आए हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। बंधुआ मजदूर, बागान मजदूर, कारखाना और प्रवासी मजदूर से संबंधित कानूनों को भी लिंग संवेदी बनाया जाएगा। सदियों पुराने पूर्वाग्रहों विशेषतया समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना, समानता प्राप्त करने में सबसे बड़ी चुनौती है। मेरी सरकार दहेज, कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूणहत्या और मानव तस्करी संबंधी कानूनों को कड़ाई से लागू करने और लिंग भेद रहित भारत बनाने के प्रति वचनबद्ध है।

बाल अधिकारों का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया गया है। सरकार बड़ी संख्या में हमारे बच्चों में कुपोषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए तैयार किए गए कई उपाय प्रारंभ करना चाहती है।

हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में लगातार अपनी पहचान बना रहे हैं। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियां जोरों पर हैं। मेरी सरकार ब्लॉक और ग्राम स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभा के विकास के लिए "पंचायत युवा खेल और क्रीड़ा अभियान" भी शुरू करेगी।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मेरी सरकार के 'अग्रणी कार्यक्रम' समावेशी शासन व्यवस्था के ढांचे की पहचान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार चाहने वालों के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का दायरा अप्रैल, 2008 से 330 जिलों से बढ़ाकर देश के सभी ग्रामीण जिलों तक करने का निर्णय लिया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में, जनवरी, 2008 के मध्य तक 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। सामाजिक लेखा परीक्षा के जरिए पारदर्शिता को कार्यक्रम कार्यान्वयन का अहम हिस्सा बना दिया गया है और यहां तक कि उपस्थिति नामावलियां भी पहली बार इंटरनेट पर उपलब्ध कराई गई हैं। यह कार्यक्रम जनता से छानबीन की अपेक्षा करता रहा है तथा यह सुनिश्चित हो कि कार्यक्रम के लाभ उन्हीं को मिलें जिनके लिए वे उपलब्ध कराए गए हैं। हमें विश्वास है कि राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं और नागरिक समाज के सक्रिय सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अपना महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाकर प्रारंभिक शिक्षा हेतु सर्वशिक्षा अभियान को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। मेरी सरकार उत्कृष्टता के अनुकरणीय मानदण्ड स्थापित करने के लिए देश के प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल के हिसाब से 6000 नए उच्च गुणवत्ता वाले मॉडल स्कूल उपलब्ध कराकर माध्यमिक शिक्षा को सभी की पहुंच में लाना चाहती है। 11वीं योजना में 30 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय, शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में 370 नए महाविद्यालय और 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 7 नए भारतीय प्रबंधन संस्थान और पुणे, कोलकाता तथा मोहाली में शुरू किए गए तीन संस्थानों के अतिरिक्त दो और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोलकर तकनीकी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि के साथ उच्चतर शिक्षा में भारी निवेश किया जाएगा। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन हमारे युवाओं की नियोजनीयता को सुनिश्चित करेगा और हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में इस समय महसूस की जा रही कौशल की कमी को दूर करेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इस मिशन के अंतर्गत अब तक 1.38 लाख उप केन्द्रों, 22,669 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 3,947 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 540 जिला अस्पतालों को संसाधन देकर उनकी मदद की गई है। अब हमारे गांवों में लगभग 5 लाख आशा (अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) और संपर्क स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार के प्रोत्साहन से जनता की बढ़ी हुई भागीदारी द्वारा ग्रामीण स्वच्छता का दायरा वर्ष 2001 में 22 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों से काफी बढ़कर आज लगभग 50 प्रतिशत हो गया है।

भारत निर्माण ने सड़कों, बिजली और टेलीफोन संपर्क द्वारा ग्रामीण भारत को विकास के अवसरों से जोड़ने की कोशिश की है। वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के अंत तक 17,000 बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है, 44,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचायी गई है, ग्रामीण निर्धनों के लिए 40 लाख मकान बनाए गए हैं, 2 लाख बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है और 36 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई व्यवस्था की गई है। इस अवधि के दौरान सभी गांवों को टेलीफोन से जोड़ने का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है। दिसम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार केवल 14,000 गांवों को जोड़ना बाकी रह गया है। गांवों में टेलीफोनों की उपलब्धता में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है।

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन का इसमें शामिल राज्यों और शहरों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वागत किया गया है। 26 राज्यों के 51 शहरों में 25,287 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके मूलभूत सेवाओं

वाले घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए 8 लाख से अधिक मकान स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति द्वारा वहनीय आवास को बढ़ावा देगी।

हमारी अवसंरचना का द्रुत आधुनिकीकरण और विकास मेरी सरकार की प्राथमिकता रही है। 68,000 मेगावाट विद्युत पैदा करने की क्षमता वाले कोयला ब्लॉकों के आबंटन सहित विभिन्न उपाय पहले ही कर लिए गए हैं। 4000-4000 मेगावाट की क्षमता वाले कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्टों (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए नौ राज्यों में नौ स्थलों का चयन कर लिया गया है और सासन और मुंधरा परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है। संयंत्रों में आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाएगी। भारत के प्रथम 540 एमडब्ल्यूई नाभिकीय विद्युत संयंत्र—तारापुर परमाणु बिजली स्टेशन की यूनिट 3 और 4 वर्ष 2007 में राष्ट्र को समर्पित की गईं जोकि हमारे स्वदेशी नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम की एक प्रमुख उपलब्धि है।

जल-विद्युत, अन्य नवीकरणीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक नीतिगत पहल की जा रही है। जैव-ईंधनों और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी राष्ट्रीय नीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र संबंधी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ऐसी विभिन्न पहलों का समर्थन किया गया जिनका उद्देश्य क्षमता में वृद्धि, किफायती कीमत-निर्धारण और विद्युत क्षेत्र में सुधार करना है।

मेरी सरकार ने घरेलू तेल और गैस भंडारों की तीव्र खोज के साथ-साथ विदेशों में अर्जन द्वारा ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने पर अधिक जोर दिया है। 15 ब्लॉकों में प्रचुर तेल व गैस के भंडारों का पता लगाया गया है। हाल ही में कोल बैड मिथेन का प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है और गहरे पानी में प्राकृतिक गैस का पहला उत्पादन भी इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। एनईएलपी-VII के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा अन्य 57 ब्लॉकों की पेशकश की जा रही है। हमारी तेल कंपनियां विदेशों में सक्रियता से ब्लॉक अर्जित कर रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक प्राधिकरण ने कार्य करना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिक शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है।

रक्षा, रेल, विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई कोयला वितरण नीति अधिसूचित की गई है। कोयला और लिग्नाइट पर रायल्टी में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से उत्पादक राज्यों को लाभ मिलेगा। एक नई खनिज नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो खनन में निवेश और रोजगार के अवसरों में अत्यधिक वृद्धि करेगी।

विद्यमान राष्ट्रीय राजमार्गों के 6500 किलोमीटर लंबे हिस्से को छह लेन का बनाने को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI के अंतर्गत 1000 किलोमीटर लंबे, पूर्णतः आवागमन नियंत्रित एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को चौड़ा करने और उनमें सुधार करने के लिए भी स्वीकृति प्रदान की है जिससे कि इस क्षेत्र के सभी 85 जिला मुख्यालयों को बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके। चालू वर्ष में प्रमुख पत्तनों पर यातायात में 13 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। प्रमुख पत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नए मॉडल रियायत करार तथा सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए टैरिफ तय करने हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुमोदन से आगामी वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होने की आशा है।

मेरी सरकार भारतीय रेल की वित्तीय और तकनीकी कार्य-निष्पादन क्षमता में बड़ा बदलाव लाई है। रेल संपर्क और अवसंरचना विकास में और सुधार करने के लिए महानगर केन्द्रों और प्रमुख पर्यटन केन्द्रों पर स्थित 22 स्टेशनों को सार्वजनिक-निजी-भागीदारी द्वारा विकसित किया जाएगा। मुंबई-दिल्ली-कोलकाता डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर रेल अवसंरचना की एक अनोखी उपलब्धि होगी जो व्यापक औद्योगिकीकरण करने में भी मदद करेगी।

यात्री और माल, दोनों प्रकार के यातायात में तीव्रतम वृद्धि के कारण नागर विमानन क्षेत्र एक अभूतपूर्व विकास के दौर से गुजर रहा है। सरकार ने हवाई अड्डा अवसंरचना का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने तथा इस क्षेत्र में दक्ष कार्मिकों की उपलब्धता में वृद्धि करने को प्राथमिकता दी है। इस वर्ष बंगलौर और हैदराबाद में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। नई दिल्ली और अन्य महानगरों में नए टर्मिनलों का निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तर-पूर्व सहित देश के विभिन्न भागों में हवाई मार्ग संपर्क बढ़ा है।

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है जिसमें प्रतिमाह 7 मिलियन से अधिक ग्राहक जुड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना करने और उसके प्रबंधन में सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है जिससे कि मोबाइल दूरसंचार सेवाओं का किफायत और शीघ्रता से विस्तार किया जा सके।

मेरी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण में वृद्धि की प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की है। सेमी कन्डक्टर फैब्रिकेशन और अन्य माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्कीम

की घोषणा की गई है। सरकार को पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-शासन योजना पूरे देश में क्रियान्वयन की उन्नत स्थिति में है। पूरे देश में लगभग 13,000 जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू कर दिया गया है। देश में उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सभी संस्थाओं को जोड़ने के लिए गिगाबाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराने हेतु एक एकीकृत राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

हमारे देश के औद्योगिक विकास के वातावरण में लगातार सुधार हो रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय उद्योग और अधिक रोजगार पैदा कर सके और विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके, सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद को उपयुक्त नीतियां सुझाने को कहा है। भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धी स्थिति, विशेषकर इस्पात और धातु-विज्ञान, वस्त्र, ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटकों, औषधीय और जैव-प्रौद्योगिकी, पेट्रोरसायन और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में, पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ है। भारत के माल निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की दर से अच्छी-खासी वार्षिक वृद्धि हुई है जिससे यह 2004-05 में 84 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2006-07 में 126.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। स्थिर नीतिगत ढांचे और व्यापार अवरोधों तथा कारोबार लागतों को कम करने के सरकार के सतत प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है।

मेरी सरकार ने हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में प्रतिवर्तन लाने पर अत्यधिक बल दिया है। 25 से ज्यादा बीमा तथा घाटे में चल रही कंपनियों के लिए पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित कर दिए गए हैं। पिछले वर्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल लाभ में 17 प्रतिशत से अधिक की उत्साहवर्धक वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनियों की लाभप्रदता 2003-04 में 5373 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2006-07 में 15567 करोड़ रु. हो गई है। इससे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में ऊर्जा का संचार हुआ है और वे बृहत विस्तार योजनाओं की ओर अग्रसर हो पाई हैं।

सरकार द्वारा प्रवर्तित विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने अब तक लगभग 100,000 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्रदान कर दिया है जबकि इससे दोगुने व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने का अनुमान है। इनमें 50,000 करोड़ रु. से अधिक का निवेश हो चुका है और इस वर्ष इनसे 67,000 करोड़ रु. का निर्यात होने की उम्मीद है।

मेरी सरकार हमारे वस्त्र उद्योग के संवर्धन के लिए वचनबद्ध है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्त्र संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित किया जाएगा। चिकित्सा प्रौद्योगिकी, जिओटेक, कृषि प्रौद्योगिकी तथा निर्माण प्रौद्योगिकी जैसे

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चार उत्कृष्टता केंन्द्र स्थापित किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम 11वीं योजना के लिए बढ़ा दी गई है।

मेरी सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के संवर्धन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इसे वित्तीय, अवसंरचनात्मक तथा विपणन सहायता प्रदान करती रहेगी।

11वीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वित्तीय सहायता में पर्याप्त वृद्धि करके सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास पर अत्यधिक बल दिया है। एक नैनो टैक्नोलॉजी मिशन शुरू किया गया है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का सफर जारी रहा है। 15 नवम्बर, 2007 को देश में ही विकसित जीएसएलवी के क्रायोजेनिक अपर स्टेज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 2007 में हमारे अपने जिओ-सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल करते हुए इनसेट-4सीआर तथा इनसेट-4बी छोड़े गए। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम ने हमें दूर-चिकित्सा, दूर-शिक्षा, दूर-संचार और अन्य सेवाओं का देश तथा विदेश, दोनों में विस्तार करने में सक्षम बनाया है। इन सफलताओं के आधार पर और आगे कार्य करने के लिए एक नए भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। भारत का प्रथम मानवरहित चंद्र मिशन 'चंद्रयान-1' इस वर्ष के अंत तक छोड़ा जाना है।

मेरी सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मामले पर तत्काल कार्रवाई की और जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके अनुकूल बनने के लिए उपयुक्त कार्यनीतियां बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद गठित की। जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की जा रही है। भारत यह सुनिश्चित करने के लिए सहर्ष तैयार है कि यहां होने वाला प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों के औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से कभी भी अधिक न हो। जलवायु परिवर्तन के संबंध में हुए बाली सम्मेलन में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रावधानों तथा सिद्धांतों के अनुसार इस मामले से निपटने के लिए दीर्घकालिक सहयोगपूर्ण कार्रवाई हेतु एक व्यापक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ रचनात्मक बातचीत की है। प्रमुख नदियों की सफाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नदी संरक्षण कार्यक्रम को नए सिरे से शुरू किया जाएगा। नव-सृजित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की नीतियों को दिशा देने के लिए पृथ्वी विज्ञान संगठन परिषद गठित की गई है। एक अत्याधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित कर दी गई है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गत वर्ष पवित्र "ऋग्वेद" को "विश्व स्मृति" रजिस्टर में दर्ज किया गया।

सरकार ने जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। दूरदर्शन के उर्दू चैनल ने सातों दिन चौबीसों घंटे सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिड रेडियो चैनलों का व्यापक विस्तार हुआ है। ऐसे 152 चैनल पहले से ही चल रहे हैं और अनुमान है कि जल्द ही इनकी संख्या बढ़कर 266 हो जाएगी। समुदाय रेडियो ने एक नई नीति के जरिए बड़े स्तर पर संवर्धन किया है। प्रिंट, दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म तथा मनोरंजन जैसे क्षेत्रों सहित भारतीय मनोरंजन तथा मीडिया उद्योग में भारी वृद्धि हो रही है जिससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पैदा हो रहा है।

पर्यटन में, देश भर में आय तथा रोजगार, दोनों के सृजन की काफी क्षमता है। "अतुल्य भारत" अभियान से भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिला है और पहली बार विदेशी पर्यटकों की संख्या 50 लाख को छू गई है। 2007 में पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय 12 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है।

आंतरिक सुरक्षा स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में है। मेरी सरकार आतंकवाद तथा वाम-पक्षीय उग्रवाद के खतरों के प्रति सजग है। जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा असम में हुए आतंकवाद के अमानवीय कृत्यों की भर्त्सना करने में पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा था। सरकार वाम-पक्षीय उग्रवाद को समाप्त कर देने के प्रयासों के प्रति कृतसंकल्प है। आंतरिक सुरक्षा पर हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने उग्रवाद तथा आतंकवाद के खतरे से लड़ने के लिए केंद्र तथा राज्यों द्वारा मिलकर काम करने की महत्ता को रेखांकित किया है। सरकार वाम-पक्षीय उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को आंतरिक सुरक्षा तथा विकास और सामाजिक रूप से शक्ति संपन्न बनाने के दोनों मोर्चों पर मदद कर रही है। पुलिस तथा सुरक्षा बलों और आसूचना संग्रहण प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर सरकार अधिक ध्यान दे रही है।

धार्मिक स्थलों के निकट रहने वालों सहित अन्य निर्दोष व्यक्तियों के प्रति होने वाले उग्र हिंसात्मक कृत्यों के समक्ष भारत की जनता घृणा की राजनीति को नकारने में एकजुट रही है। हमारी जनता का उत्तेजित न होना एक बार फिर हमारे सहज मानववाद तथा हमारे राष्ट्र की एकता व अखंडता, बहुलवाद तथा पंथ-निरपेक्षता के हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाता है। मुख्यत: इसी प्रकार देश भर में सांप्रदायिक सद्भावना तथा सौहार्द का वातावरण है। मेरी सरकार ऐसे किसी भी समूह के असामाजिक तथा राष्ट्र-विरोधी षड्यंत्रों के प्रति सदा सतर्क रहेगी जो हमारे गणराज्य की कानून और व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भावना तथा एकता और अखंडता को विघटित करने के इरादे से होंगे।

मेरी सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर में शांति, सामान्य स्थिति तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए बहु-आयामी रणनीति पर कार्य कर रही है। विद्युत तथा रोजगार सृजन सहित संपर्क तथा अवसंरचना के सुधार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना तेजी से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के एक भाग के रूप में राज्य में कश्मीरी प्रवासियों के लिए आवास परियोजना चलाई जा रही है।

आप जानते हैं कि मेरी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सभी वर्गों के लोगों के साथ गोलमेज सम्मेलनों का सिलसिला शुरू किया था। इन विचार-विमर्शों से राजनीतिक और विकासात्मक मसलों पर व्यापक नागरिक और राजनीतिक सर्वसम्मति प्रतिबिंबित होती है। सरकार समाज के सभी वर्गों का विश्वास बढ़ाने, नियंत्रण रेखा के आर-पार यात्रा को आसान बनाने तथा जम्मू और कश्मीर की जनता को बेहतर शासन तथा उनकी आकांक्षाओं पर निकटता से ध्यान देने के उद्देश्यों से एक सर्वांगीण दृष्टिकोण पर कार्य कर रही है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संपर्क में सुधार लाना, अवसंरचना का विस्तार करना तथा रोजगार सृजित करना मेरी सरकार की पहलों का केन्द्र बिन्दु रहा है। उत्तर-पूर्वी परिषद, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 18 हवाई अड्डों के उन्नयन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रही है। असम तथा अरूणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। उत्तर-पूर्वी परिषद ने इस क्षेत्र के लिए एक समर्पित एयरलाइन स्थापित करने की पहल की है। 43,000 करोड़ रु. के वित्तपोषण से उत्तर-पूर्व में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) इस क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, सुधार और उन्हें चौड़ा करने के लिए तैयार किया गया है। ट्रांस-अरूणाचल प्रदेश हाईवे राज्य की लंबाई में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बनाया जाएगा। क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। संचार तंत्र में सुधार करने के लिए ब्रॉडबैंड तथा बेतार संपर्क में और वृद्धि की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में की गई नई पहलों में नए विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की अन्य संस्थाओं की स्थापना शामिल है। उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। असम गैस क्रैकर परियोजना पर कार्य प्रारंभ हो चुका है जिससे क्षेत्र के औद्योगिक विकास में और वृद्धि होगी।

सरकार विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की उपलब्धियों तथा राष्ट्र के लिए उनके योगदान को अत्यंत महत्व देती है। उनके योगदान का सम्मान करते हुए कई पहलें की गई हैं। पहला भारतीय मूल के लोगों का विश्वविद्यालय प्रारंभ होने वाला है। भारतीय डायस्पोरा के संसाधनों को काम में लाने के लिए प्रधान मंत्री की भारतीय मूल के लोगों की वैश्विक सलाहकार परिषद

गठित करने का निर्णय किया गया है। संभावित प्रवासी कामगारों को मदद देने तथा विपत्ति में फंसे प्रवासी कामगारों की सहायता करने के लिए, "प्रवासी कामगार संसाधन केंद्र" तथा "प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद" की स्थापना की जा रही है।

मेरी सरकार ने हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण तथा कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तथा देश में रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे सशस्त्र बल हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, विद्रोही गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने में मदद करते हैं तथा आपदा प्रबंधन और आवश्यक सहायता तथा पुनर्वास का प्रबंध करने में सिविल प्राधिकारियों की बहुमूल्य सहायता करते हैं। सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 से सेवा कार्मिकों को कोर्ट मार्शल के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा तथा सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु सार्थक अवसर मिलेगा। अग्नि-III मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण तथा ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को हमारे सशस्त्र बलों में शामिल करना हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी के उन्नयन में मील के पत्थर सिद्ध हुए हैं।

मेरी सरकार की विदेशी नीति त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास को सुगम बनाने तथा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमारे क्षेत्र में विश्व में शांति तथा स्थिरता के वातावरण को बढ़ावा देना चाहती है। सरकार ने हमारे सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगात्मक रिश्ते विकसित करने तथा महाशक्तियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के कारगर प्रयास किए हैं। भारत ने अप्रैल, 2007 में नई दिल्ली में हुए 14वें सार्क शिखर सम्मेलन से लेकर अब तक सार्क को सुदृढ़ करने के सभी प्रयास किए हैं और इसे घोषणात्मक चरण से कार्यान्वयन चरण की ओर बढ़ाया है। सार्क विकास निधि, दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय तथा सार्क फूड बैंक की स्थापना के क्षेत्र में प्रगति हुई है।

हमारा ध्येय है कि हमारे पड़ोस में शान्ति, स्थायित्व और समृद्धि बनी रहे। भारत, नेपाल को इसके राजनीतिक परिवर्तन के दौर में, इसके विकास के लिए पूरी सहायता करने के लिए वचनबद्ध है। भारत, एक लोकतांत्रिक, स्थिर और संपन्न राष्ट्र के लिए, परिवर्तन काल में नेपाली लोगों की अभिलाषाओं को पूरा करने में मदद देने के लिए भी तैयार है। एक निकट और मित्र पड़ोसी के नाते हम बंगलादेश को एक शान्तिपूर्ण, स्थिर और उदार लोकतंत्र के रूप में देखना चाहेंगे। हम आशा करते हैं कि बंगलादेश की जनता पूर्ण लोकतंत्र की बहाली के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मार्फत अपनी इच्छा को व्यक्त करेगी। श्रीलंका में हिंसा की घटनाओं में दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि हुई। हमारा स्पष्ट विचार है कि नस्ली विवादों का समाधान सैन्य बल नहीं कर सकता। यह जरूरी है कि एक संगठित श्रीलंका की संरचना के भीतर बातचीत करके एक ऐसा राजनीतिक हल खोजा जाए जो समाज के हर वर्ग को स्वीकार्य हो। हम अफगानिस्तान की, इसके पुनर्निर्माण में और एक बहुलवादी और

समृद्ध समाज के निर्माण में जो भी मदद कर सकते हैं, करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और एक अच्छे पड़ोसी के संबंधों के लिए वचनबद्ध हैं। एक स्थिर, संपन्न और आंतरिक शांति संपन्न पाकिस्तान में हमारे पूरे क्षेत्र की भलाई है। जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, हम आपसी विश्वास पैदा करने और लंबित विवादों को आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ वार्ता-प्रक्रिया पुनः आरंभ करेंगे। हम आशा करते हैं कि म्यांमार में चल रही राष्ट्रीय मेल-मिलाप और राजनीतिक सुधार प्रक्रिया और इस प्रक्रिया को गति प्रदान करने की आवश्यकता की पहचान, इसे और समावेशी बनाएगी ताकि वहां शान्तिपूर्ण और स्थिर लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित हो सके।

भारत, चीन लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसके साथ हमारी शान्ति और समृद्धि के लिए कार्यनीतिक और सहकारी साझेदारी है, के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को उच्च महत्व देता है। गत माह प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान 21वीं सदी के लिए साझी दृष्टि पर हस्ताक्षर होने से यह साझेदारी और व्यापक बनी है और इसे वैश्विक विस्तार मिला है। चीन के साथ हमारी सीमा पर शान्ति और अमन-चैन बना हुआ है और दोनों देश इसे बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं।

मेरी सरकार ने विश्व की बड़ी ताकतों के साथ हमारे संबंधों में तेजी से सुधार किए हैं। विगत कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है और अब ये उच्च प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कृषि, शिक्षा और व्यापार तथा अन्य संपर्कों सहित अनेक क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य मित्र देशों के साथ असैन्य नाभिकीय सहयोग संभव होगा। सरकार रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी मित्रता को और आगे विकसित करने पर काम कर रही है। नवम्बर, 2007 में प्रधानमंत्री की मास्को यात्रा से रूस के साथ हमारी सामरिक साझेदारी और सुदृढ़ हुई है। हम यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ अलग-अलग और सामूहिक रूप से अपने संबंधों को महत्व देते हैं। 8वां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन-नवम्बर, 2007 में नई दिल्ली में हुआ था। अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया और फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे।

सरकार ने नवम्बर, 2007 में सिंगापुर में आसियान-भारत और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेकर अपनी 'लुक ईस्ट पॉलिसी' के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत जापान के साथ अपनी साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए निरन्तर काम कर रहा है। अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भारत के बढ़ते रिश्तों को अक्तूबर, 2007 में प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा और 2007 में ब्राजील और मैक्सिको के राष्ट्रपतियों की भारत यात्राओं से और बल मिला है। अक्तूबर, 2007

में प्रिटोरिया में हुए दूसरे आईबीएसए शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। भारत इस वर्ष अप्रैल में पहले भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

हमने खाड़ी क्षेत्र, जो कि 45 लाख से अधिक भारतीयों का घर है और एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझीदार है और हमारे तेल और गैस आयात का एक प्रमुख स्रोत है, के देशों के साथ अपने आपसी तालमेल का काफी विस्तार किया है। पश्चिमी एशिया के देशों के भारत के साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध हैं और वे हमारे बढ़े हुए पड़ोस का हिस्सा हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में होने वाली हलचलों से हमारे हितों और सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। भारत इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इन देशों के साथ सहयोग करना चाहता है। सरकार इराक में हो रही घटनाओं पर नजर रखे हुए है और आशा करती है कि इराक में शीघ्र ही शान्ति और स्थिरता बहाल होगी। सरकार ने नए सिरे से शुरू हुई इजराइली-फिलिस्तीनी वार्ता का भी समर्थन किया है और यह अपने पड़ोसियों के साथ शान्तिपूर्ण तरीके से रहते हुए एक स्वतन्त्र फिलिस्तीनी राष्ट्र बनने से सम्बन्धित मुद्दों के शान्तिपूर्ण समाधान की आशा करती है। यह दु:ख की बात है कि गाजा और वैस्ट बैंक में हुई हाल की घटनाओं ने फिलिस्तीन की जनता को दयनीय कष्ट तथा तंगहाली में डाल दिया है। भारत फिलिस्तीनी जनता को अतिरिक्त सहायता देगा और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद के लिए तैयार है।

भारत अपने दूरवर्ती पड़ोसी के केंद्रीय एशियाई देशों के साथ ही सहयोग का दायरा बढ़ाने के लिए संबंध विकसित कर रहा है। एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में भारत ने क्रमश: अगस्त और नवम्बर, 2007 में हुई शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार-प्रमुखों की बैठकों में भाग लिया। भारत-रूस-चीन के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय वार्ता भी काफी फलदायी हो रही है।

जैसा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना में व्यक्त किया गया है, भारत सार्वभौमिक, गैर-विभेदकारी और व्यापक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए अभी भी वचनबद्ध है तथा हमने सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण, विशेष रूप से नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए नए सिरे से आवाज उठाई है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रतिवर्ष महात्मा गांधी की जयन्ती को अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे आम सहमति से स्वीकार कर लिया गया था। पहला अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 अक्तूबर, 2007 को मनाया गया।

सरकार ने व्यापार वार्ताओं के विश्व व्यापार संगठन के दोहा विकास दौर में एक रचनात्मक भूमिका निभायी है और हमारे विकास के लिए बेहतर विदेशी आर्थिक

वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझीदारों और क्षेत्रीय समूहों के साथ व्यापार और आर्थिक साझीदारी के करार करने के लिए वार्ताओं को आगे बढ़ाया है। भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार पर वार्ताओं को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। भारत ने आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम किया।

माननीय सदस्यगण, भारत प्रगति कर रहा है। हमारे युवाओं में कुछ कर गुजरने की ललक है और समाज के कमजोर वर्गों की कुछ आकांक्षाएं हैं। हमारे सामने बाह्य और घरेलू खतरों के बावजूद विकास प्रक्रिया को बनाए रखने की चुनौती है। भारत के लोगों में सार्वभौमिक विकास को ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है। मेरी सरकार विवेकपूर्ण और ठोस आर्थिक प्रबंधन के द्वारा ऐतिहासिक रूप से उच्च वृद्धि दरों को लगातार बनाए हुए है। इससे विकास प्रक्रिया में स्थिरता और नीति में पूर्वसूचनीयता और पारदर्शिता आयी है। यह निवेश दर में वृद्धि और केंद्र तथा राज्य सरकारों, दोनों के कर राजस्व में आए उछाल से परिलक्षित होती है। आपका नेतृत्व हमारे लोगों की पूर्ण क्षमता को उजागर कर सकता है और हमारी विकास प्रक्रिया में स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित कर सकता है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि इस वर्ष संसद की कार्यवाही उद्देश्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और फलदायी होगी।

आज विश्व इस महान लोकतंत्र को, पहले से भी अधिक आशाओं और आकांक्षाओं से भरी नजरों से देख रहा है। एक स्वतंत्र समाज और एक खुली अर्थव्यवस्था के ढांचे के अंतर्गत लाखों लोगों को गरीबी, अनभिज्ञता और बीमारी से मुक्ति दिलाने की हमारी क्षमता सदैव सार्वभौमिक महत्व की रही है। ऐसे समय में, जब लोकतांत्रिक जीवन असहिष्णुतावादी ताकतों के नए दबाव का सामना कर रहा है, बहुलवादी, पंथनिरपेक्ष और समावेशी लोकतंत्र के रूप में भारत की सफलता उन लाखों लोगों को आशा की नई किरण दिखाती है जो देशोन्माद, उग्रवाद के बढ़ने और पृथकता तथा घृणा की विचारधाराओं से चिंतित हैं।

माननीय सदस्यगण, आप में से प्रत्येक को यह याद रखना है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में, आप जो करते हैं, वह न केवल आपके अपने मतदाताओं, बल्कि हमारे सभी लोगों, और हमारे क्षेत्र तथा विश्व के कोने-कोने में शांति और स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों में नई आशाएं जगाता है। इसलिए, लोकतंत्र के इस प्रतिष्ठित सदन के भीतर जो आप कहते हैं और करते हैं, उसका प्रभाव न केवल हमारे लोगों की नियति पर, बल्कि लोकतंत्र और पूरे विश्व में स्वतंत्र समाज के भविष्य पर भी पड़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ आप सबको एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।

जय हिन्द।